रिकाम्या कंटेनर यार्डमधील कामकाज सुरळीत करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) लागू; रिकाम्या कंटेनर यार्डसाठी देयके (पेमेंट) भरण्यासाठी शिपिंग लाइन्स

मुंबई, 24 ऑक्टोबर 2024: भारताचे सर्वोत्तम कामगिरी करणारे बंदर असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरणाने 19 सप्टेंबर 2024 रोजी माननीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या निर्देशानुसार, रिकाम्या कंटेनर यार्डमधील कामकाज सुव्यवस्थित करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली लागू करून रिकाम्या कंटेनर यार्डशी संबंधित चिंता दूर करण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना केल्या आहेत. हे निर्देश देते की शिपिंग लाइन्सने पैसे गोळा करावेत आणि रिकाम्या कंटेनर यार्डला पेमेंट करावे जेणेकरून रिकामे कंटेनर रिकाम्या कंटेनर यार्डमध्ये थांबू नयेत.

मानक कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहेतः

● हाताळणी शुल्काची ऑनलाईन देयके सर्व डेपो कार्यकारी सदस्यांद्वारे स्वीकारली जातील.

● वाहतूकदारांच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी आणि व्यापार अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि देयकांमधील गुंतागुंत टाळण्यासाठी, ईसीवाय प्रचालकांना (ऑपरेटर्सना) सर्व देयके शिपिंग लाइन्सद्वारेच दिली जातील आणि वाहतूकदार रिकाम्या कंटेनर यार्ड डेपोत पोहोचण्यापूर्वी पूर्णपणे पेड डिलिव्हरी ऑर्डर तयार असावी.

● डेपो कंटेनरचे सर्वेक्षण करेल आणि शिपिंग लाइन्स मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) प्रमाणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे रिकामे कंटेनर उतरवेल.

● मुदत संपलेल्या रिकाम्या स्वीकृती पत्रासह यार्डात येणाऱ्या कोणत्याही वाहतूकदाराला शिपिंग लाइनकडून वैध कागदपत्रे मिळेपर्यंत ग्राह्य धरले जाणार नाही. हे शिपिंग लाइन मानक कार्यप्रणालीनुसार (एसओपीनुसार) आहे.

भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स) आणि व्यापार विभागाचे संयुक्त सचिव, आईआरटीएस डॉ. सुरेंद्र कुमार अहिरवार यांनी 26 सप्टेंबर 2024 रोजी जनेप प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री उन्मेश शरद वाघ, भा.प्र.से., यांच्या उपस्थितीत हितधारकांशी चर्चा करण्यासाठी जनेप प्राधिकरणाला भेट दिली.

रिकाम्या कंटेनर यार्डबाबतच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी, जनेप प्राधिकरणाने आपल्या आवारातील रिकाम्या कंटेनरच्या साठवणीसाठी सुमारे 3.51 हेक्टर जागा निश्चित केली आहे. ऑपरेटरच्या निवडीसाठी या आधीच 28 सप्टेंबर 2024 रोजी निविदा काढण्यात आली आहे. तसेच, आणखी एक रिकामे कंटेनर यार्ड विकसित करण्यासाठी 26.20 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. प्रचालकाच्या (ऑपरेटरच्या) निवडीसाठी लवकरच निविदा काढली जाईल. तर एकूण 30 हेक्टर (अंदाजे) जनेप प्राधिकरण अंतर्गत या रिकाम्या कंटेनर यार्डमध्ये रिकामे कंटेनर साठवण्यासाठी/रचण्यासाठी जमीन उपलब्ध होईल, ज्यामुळे व्यापाराकरीता बराचसा वेळ आणि खर्च वाचेल.

या उपक्रमांमुळे रिकाम्या कंटेनर यार्डसाठी जागेची कमतरता दूर करण्यात, कंटेनरचे कामकाज सुव्यवस्थित करण्यात आणि बंदरावरील कार्यक्षमता वाढविण्यात लक्षणीय योगदान मिळेल.

जनेप प्राधिकरण बद्दल:

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जनेप प्राधिकरण) हे भारतातील प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदरांपैकी एक आहे. २६ मे १९८९ रोजी स्थापना झाल्यापासून, जनेप प्राधिकरण एक बल्क कार्गो टर्मिनलवरून देशातील प्रमुख कंटेनर बंदरात रूपांतरित झाले आहे.

सध्या, जनेप प्राधिकरण पाच कंटेनर टर्मिनल्स चालवते - एन एस एफ टी , एन एस आय सी टी, एन एस आय जी टी, बी एम सी टी आणि ए पी एम टी बंदरात सामान्य मालवाहतुकीसाठी उथळ पाण्याचा बर्थ देखील आहे. जनेप प्राधिकरण पोर्टवर उपस्थित असलेले लिक्विड कार्गो टर्मिनल बीपीसीएल-आयओसीएल कन्सोर्टियमद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. याव्यतिरिक्त, नव्याने बांधलेला किनारी धक्का इतर भारतीय बंदरांना जोडतो आणि किनारपट्टीवरील कंटेनरची वाहतूक वाढवते.

277 हेक्टर जमिनीवर वसलेले, जनेप प्राधिकरण भारतातील निर्यात-केंद्रित उद्योगांना चालना देण्यासाठी, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह, काळजीपूर्वक डिझाइन केलेले बहुउत्पादक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) देखील चालवते.

जनेप प्राधिकरण महाराष्ट्रातील वाढवण येथे सर्व हवामानात काम करण्यायोग्य, २० मीटर नैसर्गिक खोल, ग्रीनफिल्ड पोर्ट विकसित करत आहे. हे जागतिक स्तरावरील सर्वोत्कृष्ट १० बंदरांमध्ये स्थान मिळवणार आहे आणि स्थापनेपासून १००% हरित बंदर असेल.

मीडिया चौकशीसाठी, कृपया संपर्क साधा:

जनेप प्राधिकरण:

अंबिका सिंग

सीनियर मॅनेजर (मार्केटिंग), जनेप प्राधिकरण

मोबाईल क्रमांक: +919920372677

ईमेल: ambikasingh@jnport.gov.in

खाली कंटेनर यार्डों में सुव्यवस्थित परिचालन करने के लिए एसओपी का संचालन प्रक्रिया लागू की गई;शिपिंग लाइनों को खाली कंटेनर यार्ड के लिए अदायगी करना प्रासंगिक होने का आश्वासन|

मुंबई, 24 अक्टूबर, 2024: जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण - भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पोताश्रय, ने सक्रिय कदम उठाए हैं, विशेष मुद्दा ,खाली कंटेनर यार्डों के लिए सुव्यवस्थित परिचालन करने का एसओपी का संचालन प्रक्रिया लागू किया है, यह माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा 19 सितंबर, 2024, निदेशानुसार किया गया है। उनकी अभिलाषा यह प्रत्यक्ष करती हे की शिपिंग लाइन्स को अदायगी एकत्र करना चाहिए और खाली कंटेनर यार्डों का ऋणपरिशोध करें ताकि खाली कंटेनरों को खाली कंटेनर यार्ड में प्रतीक्षा न करना पड़े।

सर्वत्र प्रचलित प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं:

●हैंडलिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान सभी डिपो ऑपरेटिंग सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

●ट्रांसपोर्टरों की चिंता को दूर करने और व्यापार को और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा भुगतान में शामिल जटिलताओं से बचने के लिए, ईसीवाई ऑपरेटरों को सभी भुगतान केवल शिपिंग लाइन्स द्वारा किए जाएंगे और ट्रांसपोर्टर के खाली कंटेनर यार्ड डिपो तक पहुंचने से पहले पूरी तरह से भुगतान किया गया डिलीवरी ऑर्डर तैयार होना चाहिए।

● डिपो शिपिंग लाइन्स एसओपी और गाइडलाइन के आधार पर कंटेनरों का सर्वेक्षण होगा और खाली कंटेनरों को उतरा जायेगा।

●कोई भी ट्रांसपोर्टर जो एक्सपायर हो चुके खाली स्वीकृति पत्र के साथ यार्ड में आता है, उसे तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे शिपिंग लाइन से वैध दस्तावेज नहीं मिल जाते। यह शिपिंग लाइन एसओपी के अनुसार है।

डॉ. सुरेन्द्र कुमार अहिरवार, आईआरटीएस, संयुक्त सचिव, ट्रेड और लॉजिस्टिक्स, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 26 सितंबर, 2024 को जेएनपीए के अध्यक्ष श्री उन्मेष शरद वाघ, आईआरएस की उपस्थिति में स्टेक्होल्डर के साथ चर्चा करने के लिए जनेप प्राधिकरण का भी दौरा किया। खाली कंटेनर यार्ड से संबंधित चिंताओं के समाधान के लिए, जनेप प्राधिकरण ने खाली कंटेनरों के यार्ड के लिए लगभग 3.51 हेक्टेयर स्थान की उपलब्धि प्राप्त की है| ऑपरेटर के चयन के लिए निविदा 28 सितंबर, 2024 को पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, एक अन्य खाली कंटेनर यार्ड भाग स्थिर 26.20 हेक्टेयर स्थान की शिनाख्त कि गयी है| ऑपरेटर के चयन के लिए निविदा का जल्दी जारी की जाएगी। इस प्रकार, में खाली कंटेनरों के भंडारण/स्टैकिंग के लिए कुल 30 हेक्टेयर (लगभग) भूमि उपलब्ध होगी, जिससे व्यापार के लिए काफी लागत और समय की बचत होगी।

ये पहल खाली कंटेनर यार्ड के लिए स्थान की कमी को दूर करने, कंटेनर परिचालन को सुव्यवस्थित करने और पत्तन पर दक्षता को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण योगदान होगी।

जनेप प्राधिकरण के बारे में:

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जनेप प्राधिकरण) भारत के प्रमुख कंटेनर-हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक है। 26 मई 1989 को अपनी स्थापना के बाद से, जनेप प्राधिकरण ने एक बल्क कार्गो टर्मिनल से देश के प्रमुख कंटेनर पत्तन में परिवर्तन किया है।

वर्तमान में, जनेप प्राधिकरण पांच कंटेनर टर्मिनलों - एनएसएफटी, एनएसआईसीटी, एनएसआईजीटी, बीएमसीटी और एपीएमटी का संचालन करता है। बंदरगाह में सामान्य कार्गो के लिए उथले पानी की बर्थ भी है। जेएनपीए पोर्ट पर मौजूद लिक्विड कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन बीपीसीएल-आईओसीएल कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नवनिर्मित तटीय बर्थ अन्य भारतीय बंदरगाहों को जोड़ता है और तटीय कंटेनरों के यातायात को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करता है।

277 हेक्टेयर भूमि पर बसा जनेप प्राधिकरण भारत में निर्यातोन्मुखी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया बहु-उत्पाद एसईजेड भी संचालित करता है।

जनेप प्राधिकरण महाराष्ट्र के वाढवण में एक सभी मौसमों में सक्षम, गहरे ड्राफ्ट वाला, ग्रीनफील्ड पत्तन भी विकसित कर रहा है। यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होने की संभावना है और इसकी स्थापना से ही 100% ग्रीन पोर्ट होगा।

मीडिया पूछताछ के लिए, कृपया संपर्क करें:

जनेप प्राधिकरण:

अंबिका सिंह

वरिष्ठ प्रबंधक (मार्केटिंग), जनेप प्राधिकरण

मोबाइल नंबर: +919920372677

ईमेल: ambikasingh@jnport.gov.in

SoPs Implemented for Streamlining Operations at Empty Container Yards; Shipping Lines to make payment for the Empty Container Yards

Mumbai, October 24th, 2024: Jawaharlal Nehru Port Authority - India's Best Performing Port, has taken proactive measures to address the concerns regarding the Empty Containers Yard by implementing Standard Operating Procedures for streamlining operations at the Empty Container Yards, as directed by the Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Shri Piyush Goyal, on September 19th, 2024. It directs that the Shipping Lines should collect the payment and make the payment to empty container yards so that transporters do not wait at the empty container yard.

The Standard Operating Procedures are as follows:

- Online payments of Handling charges shall be accepted by all Depot Operating Members.
- To address the concern of the Transporters and further facilitate trade and also to avoid complications involved in payments, all the payments to ECY operators shall be made by Shipping Lines only and a fully paid delivery order should be ready before the transporter reaches the empty container yard depot.
- The depot will survey the containers & Offload the empty containers based on the Shipping Lines SOP and guidelines.
- Any Transporter who approaches the yard with an expired Empty Acceptance letter will not be entertained until they get the valid documents from the Shipping Line. It is as per the shipping line SOP.

Dr. Surendra Kumar Ahirwar, IRTS, Joint Secretary, Logistics and Trade, Ministry of Commerce and Industry, GoI, also visited JNPA to have a discussion with the stakeholders in the presence of Shri Unmesh Sharad Wagh, IRS, Chairman, JNPA, on September 26th, 2024.

To further resolve the concerns regarding the Empty Container Yard, JNPA has identified a space of around 3.51 Hectares for the storage of empty containers in the yard. The tender for the selection of an operator is already been issued on September 28th, 2024. Also, a space admeasuring 26.20 Hectares has been identified to develop another Empty Container Yard. The tender for the operator's selection will be issued soon. So a total of 30 Hectares (Approx.) of land will be available for the storage/stacking of empty containers at these Empty Container Yards, within JNPA, saving considerable cost and time for the Trade.

These initiatives will significantly contribute to alleviating the shortage of space for the Empty Containers Yard, streamlining container operations and optimizing efficiency at the port.

About JNPA:
The Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) is one of the premier container-handling ports in India. Since its inception on May 26, 1989, JNPA has transformed from a bulk cargo terminal into the premier container port in the country.

Currently, JNPA operates five container terminals - NSFT, NSICT, NSIGT, BMCT and APMT. The Port also has a Shallow Water Berth for general cargo. A Liquid Cargo Terminal present at the JNPA Port is managed by the BPCL-IOCL consortium. Additionally, the newly constructed coastal berth links other Indian ports and facilitates enhancing the traffic of coastal containers.

Nestled across 277 hectares of land, JNPA also operates a meticulously designed multi-product SEZ, with state-of-the-art infrastructure, to boost export-oriented industries in India.

JNPA is also developing an all-weather, deep-draft, greenfield port at Vadhvan, in Maharashtra. It is poised to be among the top 10 ports globally and will be 100% green port since its inception.

For media enquiries, please contact:
JNPA:
Ambika Singh
Sr. Manager (Marketing), JNPA
Mob: +919920372677
E-mail: ambikasingh@jnport.gov.in